श्री सभापति : प्रो. मनोज कुमार झा। आपके बाद छाया वर्मा जी भी हैं, इसलिए समय का ध्यान रखिएगा।

Need to include caste-based socio-economic parameters in Census, 2021

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) **:** सर, सौहार्दपूर्ण बंटवारा रहेगा। महोदय, इस विषय को आपके संज्ञान में लाने का अक्सर देने लिए पुनः धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन में पहले भी यह बात रखी थी कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही है? एक बार हमने जनगणना की थी, जिसमें करोड़ों रुपये खर्च किए और कहा कि data manipulate हो गया। इस आधुनिक युग में अगर ऐसा हो रहा है तो यह विडम्बना की परिस्थिति है। मेरा आग्रह है कि अभी sub-categorization की बात हो रही है, एक कमीशन को बार-बार extension मिला है। महोदय, दुनिया के किसी भी मुल्क में affirmative action या reverse discrimination में जब कोई बदलाव होता है तो evidence generate किया जाता है। हमारे यहां वह evidence कहां है, वह evidence कहां से आएगा? वह evidence तभी आएगा, जब हम SECC data लें - चूंकि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि 50 परसेंट सीलिंग को revisit करें। सर, सीलिंग को revisit करना, sub-categorization - आदि के लिए आवश्यक है कि जब वर्ष 2021 की जनगणना हो, तब जातिगत जनगणना हो, उसमें ये मुद्दे जोड़े जाएं, देश में अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग दलों के बीच में एक आम राय है कि यह पता चले कि ठेला चलाने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, सब्ज़ी बेचने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, श्रम को औने-पौने दाम पर बेचने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, खेतिहर मज़दूर की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है।

सभापति महोदय, यहां सरकार के वरिष्ठ मंत्री लोग बैठे हुए हैं, मेरा आग्रह है कि कृपापूर्वक इसको करवाइए, ताकि जब आप वर्गीकरण करें, तब आपके पास evidence हों, धन्यवाद, जय-हिन्द।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

PROF. RAM GOPAL YADAV (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): सभापति महोदय, जब जनगणना होती है, तब जातिगत जनगणना की बात ऊपर उठकर आती है। इसी बात को भांपते हुए प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2019 के चुनाव में घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी, तो जातिगत जनगणना कराएंगे। जनगणना में करोड़ों रुपये फूंक दिए जाते हैं, लेकिन जाति के आंकड़े नहीं निकल कर आते हैं तो इन करोड़ों रुपये फूंकने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। महोदय, सरकार पिछले नीतिगत निर्णयों का हवाला देती है। सरकार नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम है, अपने मित्रों के लिए नीतिगत निर्णय लेने में तनिक भी देर नहीं करती, उनके लिए नीतिगत निर्णय तुरंत लागू कर देती है। इस षड्यंत्र के पीछे क्या राज़ है, यह मुझे समझ में नहीं आता। सरकार गधा, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस आदि की गणना कराती है, किसके घर में टी.वी. है, किसके घर में फ्रिज है, किसके घर में दो पहिये की गाड़ी है, किसके घर में चार पहिये की गाड़ी है, इसकी भी गणना कराती है, लेकिन जातिगत जनगणना के पीछे रिपोर्ट न आना समझ से परे है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह तत्काल जातिगत जनगणना कराए, ताकि जाति के लोगों को उनके अधिकार मिल सकें।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SHAMSHER SINGH DULLO (Punjab): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need for release of MPLADS funds

SHRI B. LINGAIAH YADAV (Telangana): *"Hon'ble Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak. I want to raise the issue regarding the release of Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) funds. My request for release of funds for the year 2019-20 is still pending. When I visited the concerned Section, I was told that the entire fund had been surrendered to the Finance Ministry. Sir, it is not only my case but also relates to the Members from both Lok Sabha and Rajya Sabha who have completed their tenure and are facing difficulty as the funds were not released even after completion of work. The Central Government has suspended the MPLADS funds for the years 2020-21 and 2021-22 in the light of the Coronavirus pandemic. All the political parties have requested that since they have to meet public needs, MPLADS funds for both the years should be released to the Members so that these funds could be spent against fighting Coronavirus pandemic".

Hon. Prime Minister and Madam Finance Minister, I demand for release of MPLAD Funds for 2020-21 and 2021-22, along with our pending dues of 2018-19 and 2019-20.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

---

* English translation of the original speech delivered in Telugu.